भारत सरकार

श्रम और रोजगार मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1197

सोमवार, 08 दिसंबर, 2025 / 17 अग्रहायण, 1947 (शक)

तेलंगाना में औपचारिक नौकरी संबंधी भावी लक्ष्य

†1197. श्री कोंडा विश्वेश्वर रेड्डीः

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सितंबर 2017 से अक्तूबर 2025 तक ईपीएफओ में कार्मिकों की निवल वेतन-निधि वृद्धि में दर्शाए गए अनुसार देश में सृजित औपचारिक नौकरियों की कुल संख्या वर्ष-वार कितनी है;

(ख) उक्त वेतन-निधि वृद्धि में तेलंगाना का हिस्सा कितना है; और

(ग) क्या सरकार का फार्मा, आईटी और रक्षा विनिर्माण क्षेत्रों में तेलंगाना के तीव्र विकास को देखते हुए, वहां औपचारिक नौकरियों के सृजन में और तेजी लाने के लिए किसी राज्य-विशिष्ट पहल का प्रस्ताव है?

उत्तर

श्रम और रोजगार राज्य मंत्री

(सुश्री शोभा कारान्दलाजे)

(क) और (ख): निवल वेतन (पेरोल) संबंधी आंकड़े इस प्रकार है:

निवल वेतन (पेरोल) आंकड़े (जुलाई 2025 तक)		
	सम्पूर्ण भारत	**तेलंगाना**
2017-18 सितंबर-17 से	15,52,940	83,249
2018-19	61,12,223	4,04,079
2019-20	78,58,394	4,38,697
2020-21	77,08,375	4,17,091
2021-22	1,22,34,625	7,57,548
2022-23	1,38,51,689	8,52,205
2023-24	1,31,48,204	8,34,751
2024-25	1,29,78,168	8,60,639
अप्रैल-25	14,31,642	83,480
मई-25	14,62,469	81,832
जून-25	19,04,535	1,32,615
जुलाई-25	21,04,360	1,37,000

जारी..2/-

आंकड़े को निम्नलिखित सीमाओं के साथ पढ़ा जा सकता है

- निवल वेतन = नए सदस्य + दोबारा जुड़ें सदस्य - बाहर निकले सदस्य
- ईपीएफओ के वेतन आंकड़े अनंतिम है क्योंकि कर्मचारी के रिकॉर्ड को अपडेट करना एक सतत प्रक्रिया है और यह बाद के महीनों में अपडेट हो जाता है।

(ग): भारत सरकार द्वारा रोजगार से जुड़ी केन्द्रीय क्षेत्र की योजना जैसे प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना शुरू की गई है। इस योजना में युवाओं के लिए रोजगार सृजन को बढ़ावा देने, कार्यबल को औपचारिक बनाने के साथ-साथ रोजगार क्षमता बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने की परिकल्पना की गई है। इस योजना की पंजीकरण अवधि दिनांक 01.08.2025 से 31.07.2027 तक दो वर्ष है और वित्त वर्ष 2025-26 से वित्त वर्ष 2031-32 की अवधि के लिए इसका 99,446 करोड़ रुपये का बजटीय परिव्यय है।

*****